डंप यार्ड बनाने की जिद क्यों पकड़े हैं अधिकारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बंधवाड़ी को अपने कुप्रबंधन से कचरे का पहाड़ बनाने वाले कामचोर अधिकारी अब आबादी वाली जगहों को डंपिंग यार्ड में तब्दील करने पर आमादा हैं। कचरा प्रबंधन में पूरी तरह फेल ये अधिकारी होटल, कंपनियों और संस्थाओं को निस्तारण प्लांट लगाकर मौके पर ही कूड़े के निस्तारण का फरमान सुनाते हैं लेकिन यही व्यवस्था खुद नहीं करते। यदि घरों से निकलने वाले कूड़े का हाथों-हाथ निस्तारण हो जाए तो डंपिंग यार्ड के लिए जगह तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और न ही गांव वालों का विरोध झेलना पड़ेगा।

रिवाजपुर गांव में डंपिंग यार्ड बनाए जाने का 16 गांवों का विरोध एक माह बाद भी जारी है। एसडीएम, तहसीलदार के होते प्रशासन इन गांव वालों से कथित अस्थायी डंपिंग यार्ड के लिए वैकल्पिक जमीन बताने का दबाव डाल रहा है। बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड भी अस्थायी तौर पर बनाया गया था लेकिन कामचोर अधिकारियों के निकम्मेपन से यहां कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया, यदि यहां कूड़ा डालना बंद भी कर दिया जाए तो इस पहाड़ को खत्म होने में कई साल लगेंगे।

इन भ्रष्ट अधिकारियों ने यदि कूड़ा निस्तारण के तरीके का बेंगलुरू, मुंबई जैसे महानगरों से अध्ययन किया होता तो यह समस्या काफी हल हो जाती।

बेंगलुरू जैसे महानगरों में कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से हाथों हाथ किया जाता है। वहां कचरे को इकट्ठा करने वाले स्थान पर ही जैविक, ठोस, अजैविक और रिसायकलेबल आधार पर अलग कर लिया जाता है। इसमें 70-80 प्रतिशत कचरा जैविक खाद, रिसायकल के लिए कच्चे माल (जैसे प्लास्टिक, एल्युमिनियम कैन, लोहा, टिन, लकड़ी, प्लाईवुड आदि) के रूप में निकल जाता है। बाकी बचे 20 से 30 प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण कर दिया जाता है। यही कारण है कि इन शहरों में कचरे के ढेर या पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे।

'स्मार्ट सिटी' के ये अधिकारी यहां के होटल-रेस्त्रां, फैक्ट्री मालिकों से तो उनके यहां निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने के लिए छोटे प्लांट लगाने का जोर डालते हैं लेकिन यही व्यवस्था खुद नहीं करते। यदि मोहल्लों से निकलने वाला कूड़ा वहीं तुरंत निस्तारित कर दिया जाए तो कचरा ढोने में होने वाले बड़े खर्चे से भी बचेंगे और पर्यावरण बर्बाद करने वाला कूड़े का पहाड़ भी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो अधिकारियों की कचरा प्रबंधन के नाम पर होने वाली लूट कमाई में हिस्सेदारी भी बंद हो जाएगी।

सबसे बड़ी बात कचरा प्रबंधन के नाम पर सरकार से करोड़ों रुपये ऐंठने वाली ईकोग्रीन कंपनी को अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं करने पर जुर्माना लगाकर दंडित नहीं किया जा रहा बल्कि उसे हर सुविधा मुहैया कराई जाती है, इससे तो बेतहर पुरानी व्यवस्था थी जिसमें बंधवाड़ी जैसे कूड़े के पहाड़ तो नहीं खड़े किए गए थे।

रिवाजपुर आंदोलन से जुड़ा भाकियू (भानु) गुट

रिवाजपुर में प्रस्तावित डंपिग यार्ड का विरोध कर रहे 16 गांव वालों को भारतीय किसान यूनियन (भानु) गुट ने समर्थन दिया है।

डंपिंग यार्ड स्थल पर बुधवार को हुई महापंचायत में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव किरणपाल ठाकुर ने मंच से कहा कि उनका संगठन जल, जंगल, जमीन, गंगा और यमुना को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आंदोलन को पूर्ण समर्थन की घोषणा के साथ कहा कि रिवाजपुर और आस-पास के गांवों में बनने वाले कूड़ाघरों का दुष्प्रभाव फरीदाबाद ही नहीं बल्कि नोएडा और आसपास के इलाकों तक फैलेगा। गाज़ीपुर, बंधवाड़ी और अलीपुर में सरकार कूड़े का ढेर नहीं बल्कि नरक का ढेर बनाने की तैयारी है। चेतावनी दी कि सभी 16 गांव एकजुट होकर हरियाणा सरकार और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का भारी विरोध करने के लिए लगातार 2024 तक बैठने के लिए तैयार हैं।

सेव फरीदाबाद के अध्यक्ष पारस भारद्वाज व ललित चौहान सरपंच ने कहा कि प्रशासन अपने हिस्से का काम भी जनता से करवाना चाहता है। वैकल्पिक ज़मीन ग्रामवासियों ने ढूंढ दी है, अब प्रशासन दबाव बना रहा है कि वहां के संभावित विरोध को रोकने का काम भी 16 गांवों की सरदारी करे। सवाल किया कि रिवाजपुर में डम्पिंगयार्ड बनाने का आदेश देने से पहले सरकार या प्रशासन ने इस क्षेत्र की जनता से कौन सा कोई मश्वरा किया था, जो अब वैकल्पिक स्थान पर जनता की सहमति बनवाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नाहरसिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन चाहे जो कर ले लेकिन किसी कीमत पर इस क्षेत्र में कूड़ाघर नहीं बनने दिया जाएगा। महापंचायत में भूपानी से कुसुम भाटी, महावतपुर से कंवरसिंह, ददसिया से कुलदीप त्यागी के साथ ही माला चौहान, लाडो ठाकुर, बिंदु, रोहताश चौधरी, जसराम, उदयवीर, ममता तिवारी (भाकियू), गब्बर चौहान(भाकियू) व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

दहशत का माहौल पैदा करने वाले फैसले लेती है मोदी सरकार : त्रिलोचन सिंह

करनाल। आरबीआई ने बीती शाम दो हजार के नोट सर्कुलेशन से बंद करने का एलान कर दिया। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। करनाल जिला कांग्रेस संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि अगर दो हजार के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया?

उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए की दो हजार के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गये? त्रिलोचन सिंह ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि वो पहले ही गलती कर चुके हैं अब फिर से उन्होंने गलती कर दी है, बगैर समय दिए पहले नोटबंदी की गई थी और अब दो हजार का नोट भी बंद कर दिया गया। ऐसे

फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बजाए कमज़ोर होती है।

कर्नाटक में हार के बाद भाजपा बौखला गई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए दो हजार के नोट वापस लेने का एलान किया गया है। नोटबंदी और जीएसटी देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाले फैसले रहे हैं।

मोदी सरकार ने भाजपा के बड़े लोगों और बड़े घरानों के पास जमा दो हजार के नोटों को बदलवाने के लिए यह एलान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में देश में हमेशा दहशत का माहौल बनाया गया है। तानाशाही फैसलों से देश की जनता को डराया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्र, ऊचानी के वैज्ञानिकों ने व्यवसायिक प्रशिक्षण करवा ग्रामीण परिवेश के लोगों का किया भला: सांसद संजय भाटिया

करनाल (आज़ाद शर्मा) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विकास केन्द्र करनाल ने केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, करनाल में पूर्व प्रशिक्षु सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें गत वर्ष में पूर्ण किए व्यवसायिक प्रशिक्षण के सभी प्रतिभागियों को सहायता सामग्री का वितरण किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया रहे। भाटिया ने प्रशिक्षुओं के उत्साह को देखते हुए बहुत प्रसन्नता जाहिर की और सभी को प्रशिक्षण को पूरा करने और सहायता सामग्री मिलने की शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि मुझे आप सबसे उम्मीद भी है की आप सब अपने व्यवसाय की शुरुआत करके परिवार की इनकम को बढ़ाएंगे। सांसद ने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की इस तरह के प्रशिक्षणों के लिए भूरी भूरी प्रसंशा की। प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि एवम् हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विस्तार शिक्षा निदेशक तथा रजिस्ट्रार डॉ बलवान सिंह मंडल ने सभी प्रतिभागियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए खूब प्रोत्साहित किया कि आप सब हमारे देश और प्रदेश का भविष्य बनाने वाले हैं। जिस प्रकार महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणीय रहती है उसी प्रकार महिलाओं को व्यवसाय में आगे बढने के लिए प्रेरित किया। मंच का संचालन कृषि विज्ञान केन्द्र करनाल के जिला विस्तार विशेषज्ञ (फार्म प्रबंधन) डॉ. विजय कौशिक ने किया। उन्होंने अतिथिगण एवम् सभी उपस्थित प्रतिभागियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया की विश्विद्यालय और हरियाणा सरकार एस सी स्कीम के तहत उनके उत्थान के लिए अनेकों व्यवसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन करती रहती है। कृषि विज्ञान केन्द्र के कॉर्डिनेटर डॉ महा सिंह ने सभी किसानों एवम् अतिथियों का स्वागत किया।

उन्होंने बताया की गत वर्ष कटिंग टेलरिंग, बेकरी, नर्सरी, दूध उत्पादन तथा फल और सब्जी परिक्षण की व्यवसायिक प्रशिक्षण करवाए गए जिसमे कुल 240 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सांसद संजय भाटिया और निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ बलवान सिंह मंडल ने सभी प्रतिभागियों को सहायता सामग्री का वितरित की। सभी प्रतिभागी सहायता सामग्री पाकर बहुत प्रफुल्लित हुए और उनमें अपना व्यवसाय शुरू करने की ललक देखने को मिली। करनाल के डिप्टी मेयर श्री नवीन ने भी सभी प्रतिभागियों को शुभकामना संदेश दिया। डॉ. किरण खोखर जिला विस्तार विशेषज्ञ मृदा ने सभी मेहमानों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस प्रोग्राम में सी एस एस आर आई करनाल के कार्यवाहक निदेशक डॉ. भटनागर, रवि, अंकित, सुषमा, डॉ कुलदीप, राकेश तथा चिराव गांव के सरपंच प्रवीन नरवाल उपस्थित रहे।

बेअदबी रोकने के लिए सरकार कड़े कानून बनाए: दादूवाल

करनाल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान तथा पंथ प्रचारक जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा है कि गुरुग्रंथ साहिब की बे अदबी करने वालों को कठोर सजा देने के लिए कानूनों में परिवर्तन किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की तरह कानून बनाया जाए। किसी भी धर्म के ग्रंथ की बे अदबी करना मानवता के खिलाफ अपराध है। इसे राकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। वह बुधवार को करनाल के डेरा कारसेवा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर डेरा कारसेवा के महासचिव इंद्रपाल सिंह ने भी जानकारियां दीं।

उन्होंने कहा कि धार्मिक गुरुओं महात्माओं को सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। इसके साथ सरकार को भी किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को पंथ के साए में रह कर काम करना चाहिए। धर्म को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए। तानाशाह अत्याचारी राजाओं का अपना धर्म नहीं होता हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी हैं। कमेटी में पदाधिकारियों के बीच तकरार खुल कर सामने आने लगी हैं।

हरियाणा टैक्स बार ने नवनियुक्त डीईटीसी सुशीला सिंह का स्वागत किया

हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मदान और उनकी टीम सुनीला सिंह डीईटीसी करनाल द्वारा ज्वाइन करने पर उनका स्वागत किया गया। मदान ने उनके समक्ष व्यापारिक स्थल की वेरिफिकेशन का मुद्दा रखा।

एसोसिएशन चेयरमैन सुरेंद्र रोहिल्ला ने कहा कि डिपार्टमेंट द्वारा डीलर के दुकान का सिर्फ वेरिफिकेशन ही किया जाए न कि विभिन्न दस्तावेज मांगे जाए। स्टेट कोऑर्डिनेटर अनीष अरोड़ा ने डीईटीसी महोदया को कहा कि व्यापारिक स्थान पर जाने से पहले इंस्पेक्टर के पास जाने की अथॉरिटी लेटर होनी चाहिए ।

स्टेट कैशियर महिंद्र सिंह ने अपील की कि व्यापारियों को नजायज तंग ना किया जाए और इस चर्चा में डीईटीसी महोदया ने आश्वासन दिया कि करनाल में किसी भी व्यापारी को नजायज तंग नहीं किया जाएगा। मीटिंग में जिला कर बार एसोसिएशन के प्रधान नवदीप पुजारा उप प्रधान योगेश अरोड़ा सचिव सुमित बठला कैशियर नितिन गोयल अमन गुप्ता शामिल थे।

करनाल-पूर्व प्रधान संजय मदान ने तमाम व्यापारियों को सूचित किया है कि त्रस्ज्ञ विभाग व्यापारिक स्थलों को जांच करने आ रहा है इसलिए निम्नलिखित बातों का? ध्यान रखें।

1. फेक्ट्री या दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए।
2. आपके पास त्रस्ज्ञ का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
3. मुख्य रूप से ये ऐंस्योर कर लेवे की जिस जगह पर आपका काम चल रहा है वह एड्रेस जीएसटी सर्टीफिकेट मे अपडेट होना चाहिए, अन्यथा इसकी 50000/- की पेनल्टी है।
4. आपके पास सेल्स और परचेज के बिल होने चाहिए.।
5. अगर आप की फेक्ट्री या दुकान किराये की है तो उस का वैलेड किरायनामा होना चाहिए।

नोट: अगर आपका काम कहीं और जगह चल रहा है और जीएसटी सर्टीफिकेट मे कोई दूसरा एड्रेस चल रहा है तो त्रस्ज्ञ ऑफिसर आप की फर्म को बोगस फर्म घोषित कर सकता और कानूनी कार्यवाही कर सकता है। इसलिए इन बातों से सभी जानकार सुरक्षित रहें।